tee for Junior Engineers but a decision has not so far been taken. Assistant Engineers with 13 years of service on Civil side and 20 years of service on Electrical side are presently being considered for promotion as Executive Engineer. .A Cadre Review Committee has been set up for Assistant Engineers. This Committee has not yet submitted its report. A proposal to grant telescopic pay scale to the Assistant Engineers who considered by Government but has not been agreed to.

Status of Rajasthan Urban Walter Supply and Sewerage Project-H

3483. SHRI RAMDAS AGARWAL: WiU the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased' to state:

(a) what is the present status of the Rajasthan-Urban Water Supply and Sewage Project-II till date;

(b) whether it is a fact that the technical clearance for the project has been issued by CPHEEO on 1st April, 1992; if so, the details thereof;

(c) whether the revived/modified Report of project-H prepared and sent back to the Ministry of Urban Development by the Rajasthan Government; and if so, when, indicating the revised estimated cost thereof; and

(d) by when it is likely to be sent to the Department concemed for onward transmission to World Bank and if there is any delay in this regard the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHAL-AKt): (a) to (c) The preliminary project proposal had been approved from technical angle by the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation on 1-4-92 at an estimated cost of Rs. 459.20 crores (tentative). In subsequent discussion with "the State Government, the proposal has been revised to Rs. 443.40 crores and this has been approved by the Planning Commission from funding angle on 16-7-92.

(d) The proposal has been sent to the Deptt. of Economic Affairs for posing to the World Bank.

MRTS for Delhi

3484. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to non-availability of funds to finance the Mass Rapid Transit System (MRTS) for Delhi, a noval scheme to attract unaccounted money from private parties for the project has beien mooted at the highest level as per the report entitled[1], Plan to Raise Black Money for Metro which appeared in the Hindustan Times of July 18, 1992;

(b) if so, what are the facts in this regard; and

(c) what is the reaction of Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHAL-AM): (a) No, Sir. There is no such proposal.

(b) and (c) Do not arise.

कन्हेर परियोजना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समझौता

3485. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्हेर परियोजना के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मध्य प्रदेश की 390 एकड़ संभावित भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों में कोई समझौता हुआ था ;

(ख) क्या इस परियोजना के अंतर्गत इस डूब क्षेत्र का विस्तार होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि मध्य प्रदेश की और अधिक भूमि इस में न आए ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जलमग्नता का क्षेत्र संशोधित किया हैं जो 253 हैक्टेयर (625 एकड़) है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से उसके क्षेत्र को जल-मग्नता के लिए सहमति प्राप्त करनी है।

उत्तर प्रदेश में टोंस नदी पर बांध का निर्माण

3486. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर उदवहन सिंचाई परियोजना हेतु एक बांध का निर्माण कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाढ़ आने पर इस बांध से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने डूब में आने वाले क्षेत्रों और पानी के बंटवारे के संबंध मे मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(घ) मध्य प्रदेश की भूमि, संपत्ति और आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) क्या केंद्रीय सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इस परियोजना का वित्तपोषण किस प्रकार से किया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ उसकी सीमा के निकट अनुमोदित टोंस नहर परियोजना के अनुसार उसी स्थान पर एक बड़े ग्रेविटेड वीयर का निर्माण शुरू किया है । तथापि यह विवाद है कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों और आबादी पर जलमग्नता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(घ) उत्तर प्रदेश ने, जहां कहीं आवश्यक हो, बधों के निर्माण द्वारा मध्य प्रदेश में प्रभावित भूमि की सुरक्षा का आश्वासन दिया है ।

(ङ०) और (च) पम्प टोंस नहर परियोजना योजना आयोग द्वारा मार्च, 1969 में अनुमोदित की गई थी । अगस्त, 1990 में संशोधित परियोजना प्रस्ताव पर, उत्तर प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश क्षेत्रों की जलमग्नता के बारे में उस राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है । उत्तर प्रदेश ने सूचित किया हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से सहमति के अभाव से वीयर का निर्माण स्थगित कर दिया गया है ।

Damage of property due to flood *in* Assam

3487. SHRI BHADRESWAR BUBA-GOHAIN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the total amount of loss of property'and crops damaged by the recent flood in Assam; "